



निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 34 पटना, बुधवार, 1 भाद्र 1939 (श0)
23 अगस्त 2017 (ई0)

विषय-सूची		पृष्ठ	
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	---	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	2-2
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	पूरक	---
	---	पूरक-क	3-4

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No 989—I, **AWNISH**, S/o Abhai Shankar, Nehru Nager patna, Have changed my name to **Awnish Shankar** onwards for all official purposes Affidavit No.- 912 Dated 27.01.2017.

AWNISH.

No 990—I, **KUMARI RAKHI**, D/o. Achal Kumar Gupta R/o. Mata Khudi Lane, Mahendru, Patna I have Changed my name from **Kumari Rakhi to Rakhee Gupta** vide Affidavit No. 253 Dated 07.12.2016.

KUMARI RAKHI.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि०को०(अधी०)—०१—०१/२०१६—४४१४
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

9 अगस्त 2017

श्री राधे श्याम सुमन, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान सम्प्रति निलंबित (संलग्न केन्द्रीय कारा, गया) के विरुद्ध मंडल कारा, सीवान के काराधीन बंदी मो० शहाबुद्दीन से नियम विरुद्ध अनधिकृत रूप से मुलाकात कराये जाने, प्रावधान के विपरीत कारा के अन्दर प्रतिबंधित सामग्रियों का प्रवेश कराने, मुलाकातियों की तलाशी में शिथिलता बरतने, बिहार कारा हस्तक के प्रावधानों का उल्लंघन करने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापक 1849 दिनांक 26.03.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 3195 दिनांक 20.12.2016 से प्राप्त आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, सारण प्रमंडल, छपरा के जाँच प्रतिवेदन में श्री सुमन के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित पाँच (05) आरोपों में से आरोप संख्या-01 को अप्रत्यक्ष/आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या-02, 03, 05 को अप्रमाणित एवं आरोप संख्या-04 को प्रमाणित पाया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक 953 दिनांक 02.03.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री सुमन से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री सुमन के द्वारा दिनांक 16.03.2017 को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि कारा हस्तक के अनुसार कारा के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पंजियों एवं अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा पंजियों में प्रविष्टि या अन्य दायित्वों की जबाबदेही उपाधीक्षक की होती है। कारा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम गेट पंजी में अंकित करना गेट वार्डर का कर्तव्य एवं दायित्व है। उपाधीक्षक कारा की स्थिति एवं महत्वपूर्ण घटनाओं को अपने प्रतिवेदन पुस्तिका में प्रतिदिन अभिलिखित कर अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जवाबदेह हैं। आरोपित का कहना है कि उपर्युक्त तथ्यों को उनके संज्ञान में नहीं दिया जाना एवं प्रत्येक गतिविधियों पर प्रभावकारी नियंत्रण नहीं रखना उपाधीक्षक का पदीय कर्तव्य के निर्वहन में विफलता एवं प्रशासनिक कार्यों के प्रति उदासीनता का द्योतक है। श्री सुमन का कहना है कि उपाधीक्षक द्वारा मुलाकात कराने संबंधी मुलाकाती आवेदन पर अपने अनुशांसा के साथ उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् उनके द्वारा विधिपूर्वक मुलाकात कराने की अनुमति दी गई थी। मुलाकात की अनुमति दिये जाने के बाद कारा हस्तक के सुसंगत प्रावधानानुसार प्रतिबंधित सामग्री के कारा प्रवेश अथवा मुलाकातियों (आगतुकों) की सघन तलाशी कारा गेट पर तैनात कक्षपाल से कराने के बाद ही मुलाकात के लिए कारा प्रवेश लिया जाना था। अतः इसमें उपाधीक्षक, अथवा अधीनस्थ कर्मियों की चूक एवं लापरवाही मानी जायेगी। ऐसे प्रतिबंधित सामग्रियों के कारा प्रवेश के लिए मूल रूप से गेट पर तैनात कक्षपाल ही उत्तरदायी है।

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सुमन द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाब की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त संचालन

पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित किया है कि काराधीक्षक ही सम्पूर्ण कारा के नियंत्री एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी होते हैं एवं आगम-निगमन पर अधीक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है। संचालन पदाधिकारी ने अपने अधिगम में उल्लेख किया है कि आरोपित पदाधिकारी का उक्त घटना में सीधी संलिप्तता प्रतीत नहीं होती है, परन्तु काराधीक्षक के रूप में इनका यह दायित्व बनता था कि कारा में होने वाले प्रत्येक गतिविधि पर इनके द्वारा प्रभावकारी नियंत्रण रखा जाय। यदि कारा में प्रवेश करने वाले आगंतुकों की सघन जाँच के लिए प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा सघन तलाशी की गई रहती तो कारा में प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश नहीं होता। यद्यपि कारा हस्तक, 2012 में विभिन्न श्रेणी के कर्मियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्य का विवरण स्पष्ट है, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा काराधीक्षक के रूप में अपने सम्पूर्ण जिम्मेवारी को भलीभांति निर्वहन करने में उदासीनता बरती गई है।

5. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुमन के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया :-

(i) तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड।

(ii) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों की रोक का दंड।

6. उपर्युक्त विनिश्चयी दंड “तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड” के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2266 दिनांक 05.05.2017 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 884 दिनांक 18.07.2017 द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रस्तावित दण्ड “देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों की रोक” का दण्ड वृहत् दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है, फलतः इस पर विभागीय स्तर पर ही निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त “तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने” संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राधे श्याम सुमन, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान सम्प्रति निलंबित (संलग्न केन्द्रीय कारा, गया) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है :-

(i) तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड।

(ii) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों की रोक का दंड।

8. इनके निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>